भारतीय उच्चायोग

ढाका

***

भारत – बंग्लादेश संबंध

एक अलग एवं स्वतंत्र देश के रूप में बंग्लादेश को मान्यता प्रदान करने वाला भारत पहला देश था तथा दिसंबर, 1971 में इसकी आजादी के शीघ्र बाद इस देश के साथ भारत ने राजनयिक संबंध स्थापित किए। बंग्लादेश के साथ भारत के संबंध सभ्यतागत, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक संपर्कों पर आधारित हैं। दोनों देशों के बीच काफी समानताएं हैं जो इनको आपस में जोड़ती हैं – साझी ऐतिहासिक एवं सामान्य विरासत, भाषायी एवं सांस्कृतिक रिश्ते, संगीत, साहित्य एवं कला के लिए लगाव। समानताएं हमारे बहुआयामी एवं विस्तृत हो रहे संबंधों में परिलक्षित होती हैं। पिछले चार दशकों से अधिक समय में दोनों देशों ने अपने संबंधों को सुदृढ़ करना जारी रखा है तथा द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक संस्थानिक रूपरेखा का निर्माण किया है।

उच्च स्तरीय यात्राएं तथा आदान प्रदान

उच्च स्तर पर नियमित यात्राओं तथा आदान प्रदान से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध उच्च स्तर पर हैं। श्रीमती सुषमा स्वराज तथा जनरल (सेवानिवृत्त) वी के सिंह ने माननीय विदेश मंत्री और विदेश राज्य मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद क्रमश: जून और अगस्त 2014 में बंग्लादेश की अपनी पहली अकेली विदेश यात्रा की।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 और 7 जून, 2015 के दौरान बंग्लादेश का राजकीय दौरा किया। इस यात्रा के दौरान 22 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर निर्णय लिए गए जिसमें भारत - बंग्लादेश भूमि सीमा करार (एल बी ए) की पुष्टि के लिखत का आदान प्रदान शामिल था। बंग्लादेश की माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना ने माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी की पत्नी स्वर्गीय श्रीमती सुव्रा मुखर्जी के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए 19 अगस्त 2015 को नई दिल्ली का दौरा किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अतिरिक्त समय में दोनों प्रधानमंत्रियों ने 24 सितंबर 2015 को न्यूयार्क में मुलाकात की।

माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने मार्च 2013 में बंग्लादेश का दौरा किया जो राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा थी। बंग्लादेश के राष्ट्रपति श्री मोहम्मद अब्दुल हामिद ने दिसंबर, 2014 के दौरान भारत का दौरा किया, जो 42 साल के बाद बंग्लादेश के किसी राष्ट्राध्यक्ष की पहली यात्रा थी। शासनाध्यक्ष / राष्ट्राध्यक्ष के स्तर पर द्विपक्षीय यात्राओं की सूची संगल्न है।

नियमित आधार पर दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच तथा मंत्री स्तर पर भी उच्च स्तर पर अक्सर यात्राएं होती हैं।

द्विपक्षीय तंत्र

भारत और बंग्लादेश के बीच 50 से अधिक द्विपक्षीय संस्थानिक तंत्र हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के नेतृत्व में एक संयुक्त परामर्श आयोग (जे सी सी) दोनों देशों के बीच शुरू की गई पहलों के कार्यान्वयन का समन्वय एवं निगरानी करता है तथा सहयोग के लिए नए अवसरों की तलाश भी करता है। 20 सितंबर, 2014 को तीसरी संयुक्त परामर्श आयोग की बैठक का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। भारत और बंग्लादेश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय तंत्रों में से कुछ की सूची संलग्न है। 1971 से दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित महत्वपूर्ण द्विपक्षीय दस्तावेजों की सूची संलग्न है।

सुरक्षा एवं सीमा प्रबंधन

सुरक्षा सहयोग के क्षेत्रों में हमारे दोनों देशों के बीच संबंध अद्वितीय हैं। सर्वोच्च स्तर पर बंगलादेश के नेतृत्व ने आश्वासन दिया है कि भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी को भी बंगलादेश के भूभाग का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुरक्षा सहयोग के लिए अपेक्षित सभी छत्रछाया करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं तथा उनकी पुष्टि की गई है। 2011 में हस्ताक्षरित समन्वित सीमा प्रबंधन योजना (सी बी एम पी) का उद्देश्य सीमा पारीय गैर कानूनी गतिविधियों एवं अपराधों पर अधिक कारगर नियंत्रण के लिए तथा भारत - बंग्लादेश सीमा पर शांति एवं अमन चैन बनाए रखने के लिए दोनों देशों के सीमा रक्षा बलों के प्रयासों में तालमेल स्थापित करना है।

भारत और बंग्लादेश के बीच 4096.7 किमी लंबी सीमा लगती है, जो सबसे बड़ी भूमि सीमा है जिसे भारत अपने किसी पड़ोसी देश के साथ साझा करता है, जिसमें से 1116.2 किमी सीमा नदी तट से संबंधित है। जून 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की बंग्लादेश यात्रा के दौरान पुष्टि के लिखत के आदान प्रदान के बाद भारत - बंग्लादेश भूमि सीमा करार (एल बी ए) लागू हो गया है। 31 जुलाई 2015 को एक दूसरे के देशों में भारत और बंग्लादेश के एंक्लेव का आदान प्रदान किया गया तथा स्ट्रिप मैप पर हस्ताक्षर किए गए। इन विद्यमान एंक्लेव के जिन व्यक्तियों ने अपनी भारतीय नागरिकता को बनाए रखने का विकल्प चुना उन्होंने 30 नवंबर 2015 तक भारत में अंतिम मूवमेंट किया।

7 जुलाई, 2014 को अंकलोस पंचाट के अनुसार भारत और बंग्लादेश के बीच समुद्री सीमा मध्यस्थता के निस्तारण ने बंगाल की खाड़ी के इस भाग के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया है, जो दोनों देशों के लिए लाभप्रद होगा।

नदियों के पानी का बंटवारा

भारत और बंग्लादेश में 54 नदियां समान रूप से बहती हैं। इन साझी नदियों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए दोनों देशों के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए जून 1972 से एक द्विपक्षीय संयुक्त नदी आयोग (जे आर सी) काम कर रहा है। लीन सीजन (1 जनवरी से 31

मई) के दौरान गंगा नदी के पानी बंटवारे के लिए 1996 में हस्ताक्षरित गंगा जल संधि आज भी संतोषप्रद ढंग से काम कर रही है।

द्विपक्षीय व्यापार

2014-15 (जुलाई से जून) में भारत द्वारा बंग्लादेश को किए गए निर्यात का मूल्य 5816.90 मिलियन अमरीकी डालर था तथा इस अवधि के दौरान बंग्लादेश से आयात का मूल्य 527.16 मिलियन अमरीकी डालर था। 2015-16 के पूर्वार्ध (जुलाई से दिसंबर 2015) में बंग्लादेश को भारत के निर्यात का मूल्य 2664.10 मिलियन अमरीकी डालर है तथा इस अवधि के दौरान बंग्लादेश से आयात का मूल्य 321.09 मिलियन अमरीकी डालर है। वित्त वर्ष 2010-11 से पिछले पांच वर्षों में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार में 24.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। द्विपक्षीय व्यापार के आंकड़ों पर अधिक ब्यौरा संलग्न है।

साफ्टा, साप्टा और आप्टा के तहत बंग्लादेश को ड्यूटी में पर्याप्त रियायत प्रदान की गई है। इसके अलावा अन्य बातों के साथ व्यापार असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से 25 मदों को छोड़कर सभी टैरिफ लाइनों को 2011 से नकारात्म्क सूची से हटा दिया गया है। जुलाई 2014 से सद्भाव के रूप में बंग्लादेश सरकार को भारतीय राज्य त्रिपुरा से टैक्स फ्री खाद्य परिवहन की अनुमति प्रदान की गई है। सीमावर्ती समुदायों की सुविधा के लिए त्रिपुरा और मेघालय में एक एक बार्डर हाट स्थापित किए गए हैं। त्रिपुरा और मेघालय दोनों ही दो और बार्डर हाट का निर्माण कर रहे हैं तथा अन्यत्र भी कुछ और बार्डर हाट का निर्माण प्रक्रियाधीन है।

विद्युत क्षेत्र में सहयोग संतोषप्रद ढंग से आगे बढ़ रहा है। बंग्लादेश भारत से लगभग 600 मेगावाट बिजली का आयात कर रहा है। कुछ निजी भारतीय कंपनियां भी बंग्लादेश में विद्युत क्षेत्र में निवेश कर रही हैं।

दोनों देशों के बीच व्यापार एवं निवेश के मुद्दों पर और ब्यौरा संलग्न है।

बंग्लादेश के लिए भारत की ओर से आर्थिक सहायता

जनवरी 2010 में बंग्लादेश की माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान भारत ने बंग्लादेश के लिए 1 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण सहायता (एल ओ सी) की घोषणा की थी। पहली ऋण सहायता के तहत कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं में से अधिकांश परियोजनाएं पूरी हो गई हैं तथा शेष परियोजनाएं पूरी होने के विभिन्न चरणों पर हैं।

जून 2015 में बंग्लादेश की अपनी यात्रा के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 बिलियन अमरीकी डालर की एक नई ऋण सहायता की घोषणा की है। नई ऋण सहायता के तहत सड़क, रेलवे, विद्युत, जहाजरानी, एस ई जेड, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा देखरेख तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रों में परियोजनाएं शामिल होंगी। दोनों देशों के बीच विकास सहयोग पर अधिक

ब्यौरा संलग्न है।

कनेक्टिविटी

सीमा पर 20 से अधिक लैंड कस्टम स्टेशन (एल सी एस) के माध्यम से सड़क मार्ग से माल की आवाजाही होती है तथा प्रचालन के लिए 20 से अधिक एल सी एस अधिसूचित हैं। अंतर्देशीय जल व्यापार एवं ट्रांजिट पर प्रोटोकाल (पी आई डब्ल्यू टी टी) 1972 से क्रियाशील है। यह 8 विशिष्ट मार्गों पर बंग्लादेश की नदी प्रणाली के माध्यम से बार्जेज / वेजल से माल की आवाजाही की अनुमति प्रदान करता है। तटीय जल मार्गों के माध्यम से कनेक्टिविटी, जिसे तटीय जहाजरानी करार पर हस्ताक्षर के माध्यम से संभव बनाया गया है, भी भारत और बंग्लादेश दोनों के लिए प्राथमिकता है। ढाका - कोलकाता, ढाका - अगरतला, ढाका - सिलांग - गुवाहाटी तथा ढाका होते हुए कोलकाता - अगरतला के बीच बस सेवाएं भी हैं। खुलना - कोलकाता बस सेवा भी शुरू होने के लिए तैयारी के उन्नत चरण पर है। दोनों देशों के बीच तीन ब्राड गेज इंटर कंट्री रेल लिंक क्रियाशील हैं जिसमें से 6 रेल लिंक मौजूद हैं तथा शहबाजपुर - कुलौरा रेल लिंक पर कार्य चल रहा है। कोलकाता और ढाका के बीच एक नियमित यात्री ट्रेन सेवा 'मैत्री एक्सप्रेस' है जो अब सप्ताह में 4 दिन चलती है। दोनों देशों की राष्ट्रीय एयरलाइंस तथा कुछ निजी एयरलाइंस ढाका, चटगांव तथा नई दिल्ली, कोलकाता एवं मुंबई के बीच प्रचालन करती हैं। अधिक ब्यौरा संलग्न है।

क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण

बंगलादेश एक महत्वपूर्ण आई टी ई सी साझेदार देश है तथा बंग्लादेश से अनेक प्रतिभागियों ने आई टी ई सी कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का लाभ उठाया है। अधिक ब्यौरा संलग्न है।

इसके अलावा प्रशासन के कार्मिकों, पुलिस, सीमा रक्षा बलों तथा सेना के लिए विशेष पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं।

सांस्कृतिक आदान – प्रदान :

ढाका स्थित इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केन्द्र (आई जी सी सी) 2010 से सांस्कृतिक गतिविधियों के सभी आयामों को शामिल करते हुए नियमित रूप से कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग में सामान्य पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के लिए तथा संस्कृति, ड्रामा, संगीत, ललित कला एवं खेल आदि में विशिष्ट पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के लिए भी बंग्लादेश के छात्रों को हर साल आई सी सी आर द्वारा छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं। 2012 से हर साल 100 सदस्यीय युवा शिष्टमंडल भारत के दौरे पर आ रहा है। भारतीय उच्चायोग पिछले 42 सालों से बंगाली साहित्यिक मासिक पत्रिका 'भारत बिचित्र' के प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक संस्करण का प्रकाशन कर रहा है। इस पत्रिका को बंग्लादेश में अपनी तरह की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका के रूप में माना जाता है तथा समाज के सभी वर्गों में इसके काफी पाठक हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों

तथा आदान प्रदान पर अधिक ब्यौरा संलग्न है।

बंग्लादेश में भारतीय समुदाय

एक अनुमान के अनुसार भारतीय समुदाय के लगभग 10,000 लोग बंग्लादेश में रह रहे हैं। अपनी कड़ी मेहनत तथा प्रबंधकीय कौशल के लिए बंग्लादेश में भारतीयों का काफी सम्मान है और साथ ही भारतीय समुदाय सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा कर रहा है। अधिकांश भारतीय रेडीमेड गारमेंट (आर एम जी) क्षेत्र से जुड़े हैं अथवा एम एन सी में शीर्ष प्रोफेशनल हैं। इंडियन एसोसिएशन, ढाका एसोसिएशन आदि के माध्यम से बंग्लादेश में भारतीय समुदाय समय समय पर कार्यक्रमों एवं सांस्कृतिक समारोहों का आयोजन करता है।

ढाका में भारतीय उच्चायोग के संबंध में उपयोगी संसाधन निम्नानुसार है :

वेबसाइट : www.hcidhaka.gov.in

फेसबुक : https://www.facebook.com/IndiaInBangladesh

ट्विटर : https://twitter.com/ihcdhaka

यू ट्यूब : https://www.youtube.com/user/HCIDhaka

भारत बिचित्र (अंक) : https://issuu.com/hcidhaka

बंग्लादेश में सहायक उच्चायोग (ए एस सी) (चटगांव और राजशाही में) :

http://www.hcidhaka.gov.in/pages.php?id=16

*****